



पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

एक साल नई मिसाल



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

संकल्प नये उत्तराखण्ड का



विकसित नये उत्तराखण्ड की तस्वीर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना:

200 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष 179 लाख (89.50 प्रतिशत) मानव दिवस सृजित, जो माह फरवरी तक के लक्ष्य 188.98 लाख मानव दिवस के सापेक्ष 94.49 प्रतिशत है।

- 56.16 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किये गये।
- 4.62 लाख परिवारों के 6.21 लाख व्यक्तियों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:

17975 समूहों, 1463 ग्राम संगठन एवं 88 क्लस्टर संगठनों का गठन कर 6221 समूहों का रिवाल्विंग फण्ड एवं 5836 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि 60343 महिला किसानों को चिन्हित कर फार्म लाइवलीहुड तथा महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता विकास किया गया।

दीनदयाल उपध्याय ग्रामीण कौशल योजना:

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित गरीब परिवारों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर न्यूनतम मजदूरी या इससे अधिक की नियमित मासिक आय वाले रोजगार उपलब्ध कराना है। दीनदयाल उपध्याय ग्रामीण कौशल योजना के वित्तीय वर्ष 2022-23 में (माह फरवरी 2023 तक) कुल 7940 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है जबकि 5783 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार से जोड़ा गया तथा 3677 द्वारा तीन माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरल मिशन:

योजना का क्रियान्वयन राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। मिशन के अन्तर्गत राज्य को तीन चरणों में कुल 6 क्लस्टर चयनित किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत विभिन्न घटकों जैसे रोड कनेक्टिविटी, पेयजल सुविधा, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। कुल चिन्हित 6 क्लस्टरों के लिए अब तक कुल प्राप्त धनराशि रु. 93.03 करोड़ के सापेक्ष माह फरवरी 2023 तक रु. 90.53 करोड़ की धनराशि का व्यव किया जा चुका है। कुल 966 कार्यों में से 865 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना:

ग्रामीण योजनान्तर्गत पात्र सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधयुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

ग्राम विकास महायोजना के लिए रु 925.60 करोड़ का बजट प्रावधान

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में रु 25 करोड़ का बजट प्रावधान

सीमांत क्षेत्र विकास योजना में रु 20 करोड़ का बजट प्रावधान

598.10 किमी. लम्बाई की सड़को के निर्माण कार्य पूर्ण कर वर्तमान तक 250 से अधिक जनसंख्या की 24 बसावटों को सड़क सम्पर्क से संयोजित कर रु 956.94 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

